Indian J. Soc. & Pol. 08 (01) : 107-108 : 2021 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 January 2021 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

जौनपुर जनपद के ग्रामीण विकास में कृषि की भूमिका

अनामिका सिंह[1]
[1]एसोसियेट प्रोफेसर, भूगोल, आर0एस0के0डी0पी0जी0 कालेज, जौनपुर, उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

ग्रामीण विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि से संबंधित मौखिक समस्याओं के अन्तर्गत समुचित ऋण सुविधाएं वर्षा की अनिश्चिता , सिंचन सुविधाओं का अपार्याप्त विकास गांवों से बाजार की ओर कृषि उत्पादो को ले जाने की व्यवस्था की कमी आदि उल्लेखनीय है। उपर्युक्त समस्याओं के साथ साथ भू0 स्वामित्व की सामाजिक व्यवस्था भी कृषि की दशाओं में पिछडेपन का एक कारण है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यकमो को कृषि विकास क सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में सिमित भू–संसाधन पर तीब्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है।

KEYWORDS: *ग्रमीण विकास, कृषि, जौनपुर, जनसंख्या*

अध्ययन क्षेत्र अन्य जनपदों की भांति भोजन, वस्त्र ,गृह, शिक्षा तथा रोजगार जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। यहॉ कृषि से संबन्धित मौखिक समस्याओं के अन्तर्गत समुचित ऋण सुविधाएं, वर्षा की अनिश्चितता, सिंचन सुविधाओं का अपर्याप्त विकास, गॉवों से बाजारों की ओर कृषि उत्पादों को ले जाने की व्यवस्था की कमी का अध्ययन किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रधानता को देखते हुए यहॉ की कृषि के विकास के नियोजन से संबंधित पक्षों पर जोर दिया गया है।

जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी सम्भाग के उत्तरी भाग में 25.24, से 26.12 उ0अक्षांशो तथा 82.7, से 83.5, पूर्वी देशांतरों के मध्य लगभग 4लाख हे0 में विस्तृत है। जनपद की कुल जनसंख्या 32,14, 926 (1991) है। जनपद में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति कृषिगत भूमि में निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। सन् 1971 में 0.16हे0 से घटकर सन् 1981 में 0.13हे0 और 1991 में मात्र 0.1 हे0 रह गया है। यहॉ पर लगभग 60प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृषि पर जीविका निर्वाह करती है। अतः अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का विकास मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, जिसके लिये सिंचाई सुविधाओं,रसायनिक उर्वरकों, शक्ति आपूर्ति , परिवहन के साधनो, विपणन व्यवस्थाओं , बीच गोदामों की उपलब्धि पर विशेष रूप से निर्भर है। इस प्रकार जनपद में निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या प्रति व्यक्ति घटती हुई कृषिगंत भूमि और भूमि संसाधन पर अधिकतम निर्भरता जनपद से संबंधित अर्थशास्त्रिया, योजना के बनाने वालों सामाजिक कार्यकर्ताओ ,भूगोलक्ताओं एंव राजनेताओं का क्षेत्र के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चिन्तन करने पर मजबूर कर दिया है।

ग्रामीण विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि से संबंधित मौखिक समस्याओं के अन्तर्गत समुचित ऋण सुविधाएं वर्षा की अनिश्चिता , सिंचन सुविधाओं का अपार्याप्त विकास गांवों से बाजार की ओर कृषि उत्पादो को ले जाने की व्यवस्था की कमी आदि उल्लेखनीय है। उपर्युक्त समस्याओं के साथ साथ भू0 स्वामित्व की सामाजिक व्यवस्था भी कृषि की दशाओं में पिछडेपन का एक कारण है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यकमो को कृषि विकास क सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र में सिमित भू–संसाधन पर तीब्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है।

जबकि उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है ऐसा अनुमान है कि अध्ययन क्षेत्र में अगले दशक में विद्यमान जनसंख्या लगभग 1.2 गुनी हो जायेगी । अतः इस जनसंख्या के लिये अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। यद्यपि गेहूँ धान एवं अन्य फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, तथपि व्यापक पैमाने पर पारम्परिक वृद्धि के तरीको के कारण प्रति ईकाई उत्पादन संतोषजनक नहीं है। कृषि की वर्तमान प्राविधि में मुख्य रूप से पूंजी के अधिमासिक निवेश पर निर्भर है , जिसमे सुनिश्चित सिंचाई के साधन अति आवश्यक है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं रासायनिक उर्वरकों तथा उच्च उत्पादकता वाले बीजों आदि के बढ़ते उपयोग के परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग प्रतिरूप में सकारात्मक परिवर्तन हुए है तथापि अध्ययन क्षेत्र में अभी भी बहुत सी भूमि ऐसी ही, जिसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उनमें गहरी जुताई उनको समतल करके अथवा कम उर्वर भूमि को अतिरिक्त उर्वरकों के उपयोग द्वारा कृषि योग्य बेकार भूमि को काम में लाया जा सकता है। वर्तमान समय में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के 36.6 प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र तथा 26.167 दो फसली क्षेत्रों को अध्ययन क्षेत्र में बढाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। यहां बहुत कम भूमि पर जायद की फसलें एवं सब्जियॉ पैदा की जाती है।

अतः अधिवासो के आस–पास जहॉ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है उपलब्ध कृषिगत भूमि को आलू, प्याज आदि फसलों के लिये अधिकधिक उपयोग किया जाना चाहिये जिससे अधिकाधिक आय प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार फसल चकम्रण तथा जायद के अन्तर्गत मूंग एवं उर्द की कृषि के प्रसार द्वारा कृषि के वार्षिक उत्पादन में व्यापक रूप से वृद्धि हो सकती है।

1: Corresponding Author

अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला है। यहॉ पर अधिकांश कार्यशील जनसंख्या कृषि एवं सहायक व्यवसायों द्वारा जीवन यापन करती है। यहां के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का आधार मुख्य रूप से कृषि है जिसके लिये कृषि साधनो में विकास अति आवश्यक है। दो तिहाई से अधिक कृषक लधु एवं सीमान्त जोत की इकाईयों के स्वामी हैं।

इसलिये व्यक्तिगत स्तर पर वे सिंचाई के साधनों की व्यवस्था आदि करने में अक्षम है। अतः प्रशासन द्वारा इस प्रकार की सुविधाओं में विकास की आवश्यकता है। वैसे विधमान नहरों में कृषि फसलों की आवश्यकता के समय जलापूर्ति के द्वारा इस समस्या का पर्याप्त समाधान सम्भव है। इसके अतिरिक्त भूमिगत जलस्तर के सधन सर्वेक्षण के पश्चात ऐसे स्थलो पर सरकार द्वारा ट्यूबेल लगवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये जहां पर वर्तमान समय में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लधु एवं सीमान्त कृषकों को ट्रैक्टर सहित कृषि ने अन्य मशीनी उपकरणों के लिये दिये जाने वाले ऋणो की व्याज दरे पर्याप्त कम की जानी चाहिए ताकि कृषक अधिकाधिक नवोन्मेष के प्रति तीब्र गति से आकर्षित है।

अध्ययन क्षेत्र सधन जनसंख्या वाला है और यहॉ जोत की इकाइयॉ अधिकांशतः छोटी है। कृषको की वित्तीय दशा संतोषजनक नहीं है। आवश्यकता की अनेक फसले थोड़ी मात्रा में ही पैदा की जाती है। ट्रैक्टर शक्ति संचालित छिड़काव की मशीने नलकूप जैसे परिमार्जित उपकरणों के खराब होने पर उनके ठीक करने की सुविधाएं विकसित की जानी चाहिये जिसके लिये प्रशासनिक स्तर पर चलती फिरती कार्यशालाओं की व्यवस्था की जानी चहिये। इसके साथ साथ ट्रैक्टर छिड़काव की मशीनों जैसे उपकरणों को किराए पर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए जिनके किराये निम्नतम स्तर पर होने चाहिये।

इस प्रकार समस्त पक्षों पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिये। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के सीमित संसाधन आधार को देखते हुए विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गो तथा कृषकों की आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिये कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। यद्यपि क्षेत्र की समस्याएं असीमित है तथापि उनमे से अधिकांश को स्थानीय जन सहयोग एवं लोगों की सक्रिय भागीदारी से सुलझाया जा सकता है।

REFERENCES

बंसल ए0सी0,(2015–16), *ग्रामीण बस्ती भूगोल,* मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन

मिश्रा आर0पी0 एवं सुन्दम, के0बी0 (1980) '*मल्टीलेबल प्लालिंग एण्ड इंटीग्रेटेड एरल डेवलपमेंट इन इण्या*', नई दिल्ली, हेरिटेज पब्लिसर्स,

मेक्डोनाल्ड, ए0एम0 (एड0) (1980) '*चेम्बर्स ऑ ट्वेंटीय सेन्चुरी डिक्सनरी*' नई दिल्ली, एलाइड पब्लिसर्स लि0,पृष्ठ सं0 681

तिवारी, आर0 सी0 तिवारी (2010), '*कृषि भूगोल*' इलाहाबाद, प्रयाग पुस्तक, पृष्ठ सं0 66